Sl. No.	Name of Project/ Capacity (MW)	Expected date of commissioning	Present Status/ Reasons for delay
4.	Brahmpuram DG Sets (5×20)	1997-98	Erection work of all DG Sets (units 5) and construction of fuel handling facilities are in progress.
5.	Malankara HEP (3×3.5)	1990-2000	Delay in the civil works. Revision in Capacity.
6.	Kayamkulam combined Cycle Power Project (GT 2×120+ST 1×160)	1998-99	At site, various infrastructural developmental works are in progress.
7.	Kuttiyadi Extn. HEP (50)	2001-02	Delay by KSEB in taking decision for execution of project.
8.	Puyankutty St. I HEP (2×120)	Beyond 9th Plan	Forest clearance is not received.
9.	Anakkayam HEP St. I (2×4)	1999-2000	Delay in starts of works/deciding executing agencies.
10.	DG Kozikhodc (6×20)	1999-2000	Details ar awaited from the State Govt.

(c) and (d) While monitoring and reviewing projects, the reasons for delay are also gone into and in order to ensure the timely commissioning of power projects, which are under execution, Ministry of Power and the Central Electricity render timely assistance, where ever required, by taking up the matter with the concerned authorites.

झारखंड क्षेत्र में सुपर ताप विद्युत संयंत्र

2036. **श्री ज्ञान रंजन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयलकर विद्युत परियोजना के निर्माण के विरुद्ध प्रतिवाद और झारखंड क्षेत्र में कोयले की प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए, झारखंड क्षेत्र में एक सुपर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के संबंध में घोषणा की गई थी तथा भूमि के सर्वेक्षण और अधिग्रहण से संबंधित कार्य को पूरा कर लिया गया था; और

(ख) क्या सरकार प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए तथा कर्मकारों और विशेषतया जन-जातीय लोगों एवं पिछड़े व्यक्तियों तथा उद्योगों के उस क्षेत्र से प्रवास को रोकने के लिए झारखंड क्षेत्र में लघु जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का विचार रखती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) ने बिहार में हजारीबाग जिले के टाण्डवा में उत्तरी करनपुरा सुपर ताप विद्युत संयंत्र (2×500 मेगावाट) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया था। स्थल संबंधी सर्वेक्षण करने के पश्चत् एन०टी०पी०सी० ने नवम्बर, 1989 में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की थी। तथापि, निम्नलिखित कारणों से यह परियोजना निवेश संबंधी अनुमोदन हेतु और आगे नहीं बढ़ाई जा सकी:—

1. यह स्थल आरक्षित एवं सुरक्षित वन्य क्षेत्र के अत्यधिक समीप होने के कारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

2. एन०टी०पी०सी० द्वारा डी०वी०सी० के क्षेत्र में परियोजना कार्यान्वित करने के संबंध में दामोदर घाटी निगम (डी०वी०सी०) द्वारा आपत्ति की गई।

3. पूर्वी क्षेत्र में अपर्याप्त मांग तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली का अभाव होने के कारण यह क्षेत्र इस परियोजना की विद्युत को नहीं खपा सकता है।

इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एन०टी०पी०सी० द्वारा इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है। तथापि, मैगा विद्युत नीति के तहत् सरकार बिहार में औरंगाबाद जिले के नवीनगर में 2000 मेगावाट की एक ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने पर विचार कर रही है जिसके लिए पावरग्रिड ने पहले ही अर्हता हेतु अनुरोध आमंत्रित कर दिए हैं।

(ख) लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है।

गुजरात में निजी और विदेशी कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

2037. **श्री चीमनभाई हरी भाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु अब तक किन-किन बहु-राष्ट्रीय कंपनियों एवं निजी कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में इसी प्रकार की विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या अहमदाबाद में विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं की स्थापना करने की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय और निजी कंपनियों द्वारा अहमदाबाद विद्युत प्रदाय कंपनी के साथ किसी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Power Requirement of Uttrakhand

2038. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have in the recent past, undertaken any survey about the total power requirement of the Uttrakhand area of Uttar Pradesh;

(b) if so, the total requirement and the actual supply of power in the area;

(c) the number of villages, district-wise not having electricity in the area and by when all villages would be given electricity; and

(d) the number of villages, provided electricity during last three years, district-wise and year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) No, Sir.

(c) The number of villages district-wise not electrified upto January, 1997 is enclosed in Statement-I (*See* below). In the draft report of the Working Group of Energy (constituted by Government of U.P.) for finalisation of 9th Five Year Plan (1997—2002) for power sector in U.P., the Government of U.P. has proposed to electrify all the remaining villages by the end of 9th Plan (by March 2002) but this will depend upon availability of required financial assistance and other inputs.

(d) No. of villages, district-wise, provided electricity during last three years, yearwise is enclosed in Statement-II.